गतिशील विकास के द्वार पर झारखंड

रघुवर दास
मुख्यमंत्री, झारखंड

लगभग पांच साल पहले झारखंड की सत्ता संभालने के बाद मैंने राज्य की सवा तीन करोड़ जनता की सेवा का संकल्प लिया था. गरीब परिवार से आया था. इसलिए गरीबों की पीड़ा का एहसास था. मुझे राजनीतिक अनिश्चितता और ठहराव के कारण राज्य को हुए बड़े नुकसान का तुरंत जायजा लेकर आम जनता तक विकास पहुंचाने की बड़ी जिम्मेवारी राज्य की जनता ने दी थी, सो रुकना कहां था? बस चलन ही था. निरंतर, ताकि राज्य की जनता के सपने पूरे हो सकें. युवाओं को रोजगार मिले. किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिले. उनकी फसल के नुकसान की भरपाई हो. महिलाओं का सशक्तीकरण हो. बच्चों को स्कूली शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण वातावरण मिले और लगातार चलते आ रहे भारी ड्रॉप आउट को शून्य स्तर पर लाया जा सके. राज्य का हर वर्ग अपेक्षाओं की बुनियाद पर टकटकी लगाये देख रहा था. जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी. इसलिए ठहरने का सवाल ही नहीं था.

आज मुझे जनता की सेवा करते हुए लगभग पांच साल हो गये. इन पांच सालों में यह तो नहीं कहूंगा कि जनता की सारी अपेक्षाएं पूरी हो गयीं, लेकिन इस बात का संतोष जरूर है कि जनता की हर उम्मीद धीरे-धीरे पूरी होने लगी है. एक सकारात्मक माहौल बना है. सरकार पर जनता का विश्वास मजबूत हुआ है. अधिकतर सेवाओं के डिजिटल हो जाने से सरकारी महकमों की कार्यक्षमता में इजाफा हुआ है और जनता को सेवा देने की राह आसान हुई है. अब सरकारी दफ्तरों में कई दिनों तक घंटों चक्कर लगाने से जनता को मुक्ति मिली है. उनकी परेशानियां कम हुई हैं. झारखंड में पांच साल स्थिर सरकार रही. इस स्थिरता का ही परिणाम है कि राज्य के विकास को गति मिली. घर-घर बिजली पहुंची. लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलीं. महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिली. बच्चियों को भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है. यह सब राज्य की जनता की वजह से हुआ, क्योंकि उन्होंने एक मजबूत और स्थिर सरकार दी.

आम जनता को सरकार से काफी अपेक्षाएं होती हैं, क्योंकि सरकारी योजनाओं के माध्यम से ही उनके गांव व शहर में बुनियादी सुविधाओं को समयबद्ध तरीके से पहुंचाया जाना संभव हो पाता है. इसमें भ्रष्टाचार एक बड़ी बाधा है. हमने राज्य के सेवक के रूप में जिम्मेदारी संभालते ही भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस का रुख अपनाया और इसका नतीजा है कि अब तक लगभग पांच सौ भ्रष्टाचारियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है या उन पर यथोचित कानूनी कार्रवाई की गयी है. राज्य में एक बड़ी समस्या नक्सलवाद का विस्तार था. एक समय था जब लगभग 16 जिले नक्सलवाद से ग्रस्त थे. इसके कारण आम जनता तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पा रहा था. हमने इस पर पूरी तरह नकेल कसने का मन बनाया और आज

सरायकेला जिले के राजनगर स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय, बड़ाकुनाबेड़ा के स्कूली बच्चों से मिलते हुए.

स्थिति यह है कि राज्य में सक्रिय लगभग 90 फीसदी नक्सली या तो आत्मसमर्पण कर चुके हैं या मारे जा चुके हैं. राज्य के विकास को पटरी से उतारने की कोशिश करनेवालों के खिलाफ सरकार हमेशा सख्त रही है. इसके अलावा किसी को भी गैर वाजिब एवं असंवैधानिक तरीके से स्थितियां बदतर करने की इजाजत नहीं दी है. हमने नक्सलियों को एक बार फिर कहा है कि या तो मुख्यधारा में शामिल हो जायें या फिर सख्ती के लिए तैयार रहें. नक्सली घटनाओं पर व्यापक नियंत्रण के कारण ही अब दूर-दराज के गांवों में अच्छी गुणवत्ता की सड़कें बनाना, घर-घर में जलमीनार के माध्यम से पानी पहुंचाना, पंचायत एवं सामुदायिक भवनों का निर्माण तथा संपर्क के लिए पुल-पुलिया का बहुतायत से निर्माण संभव हो पाया है. हम यह सब आम जनता के लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि हम आम जनता के प्रति जवाबदेह हैं. बुनियादी सुविधाएं, सुरक्षित माहौल और तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करना जनता का हक है और उनके हक में हम किसी को भी सेंधमारी करने नहीं दे सकते हैं.

पिछले कुछ वर्षों में व्यापक जनोपयोगी योजनाओं की उपलब्धता से जन-जन में एक नया विश्वास कायम हुआ है. केंद्र की सभी योजनाएं झारखंड में पूरी शक्ति से हम लागू कर रहे हैं. अभी हाल ही में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना एवं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हमने राज्य के किसानों तक राशि पहुंचाने का काम किया है. मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत पहली किस्त के रूप में हमने 10 अगस्त 2019 को 13 लाख 60 हजार किसानों को 482 करोड़ की राशि उनके खाते में भेजी. दूसरी किस्त के रूप में 11 अक्तूबर 2019 को योजना से छूटे हुए 11 लाख 51 हजार 137 किसानों के खाते में 452 करोड़ की राशि भेजी. इस तरह पहली और दूसरी किस्त के तौर पर राज्य के 26 लाख किसानों के बीच 900 करोड़ रुपये से अधिक वितरित की गयी है. नवंबर-दिसंबर, 2019 तक तीसरी किस्त की राशि भी किसानों के खाते में भेज दी जायेगी. इस तरह से राज्य के 35 लाख किसानों के खाते में राज्य सरकार तीन हजार करोड़ रुपये उनकी आर्थिक समृद्धि एवं कृषि संसाधन जुटाने के लिए प्रदान करेगी. इससे किसान भाई-बहनों में उत्साह दिख रहा है. हम अपने किसान भाई-बहनों को विश्वास दिलाते हैं कि उनकी हर समस्या के समाधान के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे.

राज्य में महिला सशक्तीकरण के लिए हमारी सरकार ने कई ऐतिहासिक कदम उठाया है. एक रुपया में महिला के नाम पर जमीन रजिस्ट्री, सखी मंडल की महिलाओं को स्वरोजगार के साधन उपलब्ध करा कर उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करना, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, उज्ज्वला योजना, मातृत्व सुरक्षा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं ने झारखंड की महिलाओं को व्यापक रूप में सशक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है. मैं खुद सारी योजनाओं की मॉनिटरिंग करता हूं, ताकि हर जरुरतमंद तक योजनाओं का लाभ पहुंच सके. राज्य में युवाओं के कौशल विकास का मामला हो या फिर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी विश्वविद्यालय से लेकर महिलाओं के लिए अलग महाविद्यालय खोलने की बात हो. हर स्तर पर हम अपने युवाओं को सशक्त और रोजगार देनेवाला बनाने की मुहिम में जुटे हैं. इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हमें दिखती है. हम इस दिशा में लगातार प्रयास करते हुए अपने युवाओं को अच्छी शिक्षा और योग्यता के अनुसार रोजगार देने में जुटे हैं. हमने राज्य में स्थानीयता की नीति लागू कर दी है, जिसका लाभ राज्य के युवाओं को अब मिलने लगा है. उनके चेहरे पर अब आत्मविश्वास दिखायी देता है. यह व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए बेहद संतोष का विषय है.

मैं जानता हूं कि पूरी व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए विराट संकल्प और सतत कर्मशीलता की आवश्यकता होती है. गरीबों की दशा में सुधार करने के लिए विस्तृत नजरिया का होना भी आवश्यक है. हमारा नजरिया बिल्कुल स्पष्ट है कि जनता तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने के लिए राज्य के सेवक को अनवरत कार्य करना होगा. सभी तंत्र भी इस दिशा में प्रयासरत रहें, तभी आम जनता तक खुशहाली पहुंच सकती है. हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम हमेशा आपके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए समग्र प्रयास करते रहेंगे.

पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा में महिला किसान से उनकी समस्या सुनते हुए व चरण पादुका योजना के तहत युवती को चप्पल पहनाते हुए.